ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

देश में प्रति व्यक्ति सीओ2 उत्सर्जन है कम

रविवारीय, 06 दिसंबर 2020 वर्ष- दो, अंक-18, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं हवाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

हृदय रोग से 2019 में 90 लाख लोगों की मौत

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हृदय रोग दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोगों की जान ले रहा है। 2019 में इसके चलते करीब 90 लाख लोगों की मौत हुई थी, जबकि 20 साल पहले यह 68 लाख मौतों के लिए जिम्मेवार था। यदि सभी कारणों से होने वाली मौतों को देखें तो उनमें से 16 फीसदी मौतों के लिए हृदय रोग जिम्मेवार हैं। यदि 2019 में हुई मौतों के 10 प्रमुख कारणों पर गौर करें तो उनमें से 7 कैंसर और मधुमेह जैसे गैर संक्रामक रोग हैं।

2019 में स्ट्रोक को दूसरा स्थान दिया है जिसके चलते करीब 62 लाख लोगों की जान गई थी। जबकि इसके बाद फेफड़े से जुड़ी बीमारी 'सीओपीडी' का नंबर आता है जिसके चलते करीब 32 लाख लोगों की मौत हुई थी। फेफड़ों के कैंसर के चलते 18 लाख लोगों की जान गई थी। रिपोर्ट के अनुसार पहली बार अल्जाइमर और डिमेंशिया को 10 प्रमुख कारकों में शामिल किया गया है, जिनके चलते 2019 में 16 लाख लोगों की मौत हुई थी। जिसमें से 65 फीसदी महिलाएं थी।

झारखंड में किसानों से धान की सरकारी खरीद पर रोक

वरीय संवाददाता

एक ओर केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष आंदोलन और विरोध में जुटा हुआ है, दिल्ली के आस पास हो रहे किसान आंदोलनों को तकरीबन सारे विपक्ष का समर्थन प्राप्त है।

झारखंड सरकार ने भी केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को किसानों के लिये नुकसानदेह बता कर इसका विरोध किया है, पर यह एक अजीब विरोधाभासी बात है कि जो झारखंड सरकार केंद्र के कृषि नीतियों के खिलाफ है, उसे किसान विरोधी बता रही है वह स्वयं झारखंड के किसानों से धान खरीदने से इनकार कर रही है। राज्य के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने राज्य के किसानों से यह कह कर धान खरीदने से मना कर दिया कि इस मौसम में धान भींगा हुआ है जिसे खरीद कर हम राज्य के खजाने को खाली नहीं कर सकते। वहीं राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इस मुद्दे पर ढुलमुल सा रवैया दिखाया है।

दरअसल किसानों के हित में बड़ी -बड़ी बातें करना , उन्हें अन्नदाता बता कर उनका महिमा गान करना, राजनीति करना तकरीबन सारे राजनीतिक दलों का प्रिय शगल है, पर हकीकत में जमीनी तौर पर किसान हित में ठोस काम करने से सबों को परहेज है। जहां एक ओर राज्य के मुख्यमंत्री किसानों के मुद्दों पर केंद्र सरकार की खिंचाई करते हैं वहीं झारखंड

में धान की खरीदी पर फिलहाल रोक पर चुप्पी साध लिये हैं। चुनाव पूर्व किसानों को ढाई हजार रूपये प्रति क्विंटल देने के बादे पर अब अमल के बजाय दो हजार पचास रूपये देने की बात सामने आ रही है। किसान हित की कई योजनाओं के बंद होने की बात भी सामने आ रही है।

झारखंड मेंमंडी सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं है और यहां धान उपज का बहुत कम प्रतिशत ही सरकारी खरीद में शामिल है। राज्य सरकार के धान खरीद पर रोक के फैसले के बाद गावों कस्बों में किसान साहूकारों के पास बहुत ही कम कीमत पर अपने खून पसीने की उपज बेच रहे हैं।

लॉकडाउन में लौटे मजदूरों और समय पर इंद्र की कृपा से इस वर्ष धान की अच्छी पैदावार हुई थी

लॉकडाउन संकट में देश भर से मजदूर इस बार जैसे तैसे अपने गांव को लौटे थे और धान रोपने के मौसम में उन्होंने जम कर खेती की। इस कारण से पूरे देश में धान की खेती का रकबा भी बढा। इसके अलावा इस साल मॉनसून ने भी भरपूर साथ दिया। झारखंड में भी इस बार समय पर बारिश होती रही और खरीफ की अच्छी फसल की उम्मीद की गयी है। ऐसे में निश्चय ही झारखंड सरकार के द्वारा किसानों के धान की फसल की खरीदी पर रोक एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पलामू प्रमंडल के कुछ किसानों का कहना है कि तैयार धान उपज की अगर सरकारी खरीद नहीं होती है तो ज्यादतर किसान धान को स्टोर कर के नहीं रखते, वो अंततः नगद पैसों की आवश्यकता के कारण औने पौने कीमत में भी धान को बेचेंगे ही। अगर वो धान को बेचते नहीं है तो भी उसके बर्बाद होने का चांस ज्यादा है।

वैसे भी केंद्र की कृषि नीतियों का विरोध एक अलग विषय है, पर झारखंड में पंजाब हरियाणा जैसी कोई मंडी सिस्टम तो है नहीं। महज 10-15 प्रतिशत धान की ही सरकारी खरीदी होती है, ऐसे में ज्यादतर किसान तो अंततः खुले मार्केट में ही अनाज बेचता है।

किसान स्थानीय साहूकारों से बेच रहे हैं धान

झारखंड में अनुमानतः 28 लाख हेक्टेयर में खेती होती है और धान ही यहां की मुख्य फसल है। इस वर्ष धान की फसल भले ही अच्छी हुई हो पर किसानों की आमदनी अच्छी नहीं हो रही है। सरकार ने धान की खरीद शुरू नहीं की है। जिसके कारण किसान अपने धान स्थानीय साहूकारों को बेच रहे हैं। इसका मूल्य उन्हें सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य से आधा मिल रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार यह कह कर धान क्रय केंद्र नहीं खोला जा रही है कि किसानों का धान अभी गीला है। इधर कई किसानों का कहना है कि धान गीला है तो फिर साहूकार कैसे ले रहे हैं। सरकार साहूकारों की जेब भरने के लिए धान क्रय केंद्र नहीं खोले जाने का फैसला लिया है।

1200 रुपये क्विंटल बेच दिए धान

एक किसान ने बताया की उसने 12 क्विंटल धान पैदा किया है। खाने भर रखकर 7 क्विंटल धान 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर बेच दिए हैं। उन्होंने कहा कि रबी फसल की बुआई के लिए धान बेचना भी जरूरी है। सरकार के गलत फैसले के कारण अब तक धान क्रय केंद्र नहीं खुला। इससे किसान आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं। जबकि अभी किसानों को रबी फसल के लिए पूंजी का भी इंतजाम करना है।

नवनियुक्त कुलपति के प्रयासों से बीएयू को मिली पहचान

कृषि विश्वविद्यालयों के रैंकिंग में बीएयू को स्थान मिला

रांचीः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर), नई दिल्ली के द्वारा चार वर्षों से कृषि शिक्षा,अनुसंधान एवं विस्तार के मानकों पर आधारित आखिल भारतीय स्तर पर कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की जा रही है. पिछले वर्ष तकनीकी भूलवश बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) इस स्पर्धा में शामिल नहीं हो सका.

नव नियुक्त कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने प्रभार लेते ही इस दिशा में गंभीर प्रयास किये. आख़िरकार कुलपति के प्रयासों ने बीएयू को राष्ट्रीय पटल पर नई पहचान दे दी है. शनिवार को आईसीएआर ने वर्ष 2019 के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की आखिल भारतीय स्तर पर रैंकिंग जारी की है. इस रैंकिंग में पहलीबार झारखण्ड राज्य के में एकमात्र कृषि शिक्षा संस्थान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को 60 वाँ रैंक दिया गया है.

पूरे देश में उच्च कृषि शिक्षा के क्षेत्र में 64 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 3 केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय तथा 4 डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत है. विश्वविद्यालय सूत्रों ने अनेकों कठिनाईयों से जूझ रहे विश्वविद्यालय के लिए इस रैंकिंग को संजीवनी बताया है. बीएयू को रैंकिंग मिलने पर विश्ववद्यालय कर्मियों में काफी खुशी देखी जा रही है.

बीएयू कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने बताया कि स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियमित रूप से कार्यरत 15 प्रतिशत प्राध्यापक व वैज्ञानिक तथा 10 प्रतिशत कर्मचारियों के बावजूद 60 वाँ रैंक का मिलना विश्वविद्यालय के लिए बड़ी सफलता है. विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में नियमित प्राध्यापक, वैज्ञानिक एवं कर्मचारी का होना पहली प्राथमिकता है. सरकार के सहयोग से इस दिशा में प्रयास किये जा रहे है. कुलपति ने कहा कि नियमित प्राध्यापक एवं वैज्ञानिकों की कमी की वजह से विश्वविद्यालय को बढ़िया रैंकिंग नहीं मिल पाया. प्राध्यापक एवं वैज्ञानिक पर अत्यधिक कार्यभार से गुणवत्ता को बनाये रखना बड़ी चुनौती साबित हो रही है. विश्वविद्यालय में एक को छोड़ सभी डीन, डायरेक्टर, एसोसिएट डीन आदि वरीय अधिकारियों के पद प्रभार में चल रहे है. अनुबंध पर नियुक्त प्राध्यापक एवं वैज्ञानिक से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है.

बेहतर रैंकिंग के लिए नियमित नियुक्ति, संकाय सदस्यों की पीएचडी अहर्ता, इंटरनेशनल जर्नल में शोध पत्रों का प्रकाशन, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन, नेशनल अवार्ड, तकनीकों का पेटेंट, छात्रों का राष्ट्रीय स्तर पर जेआरएफ, एसआरएफ एवं एआरएस एग्जाम में सफलता, छात्रों का प्लेसमेंट, विदेशी छात्रों का नामांकन, राष्ट्रीय खेल -कुद में सफलता के लिए प्रयास शुरू किये जा रहे है. आने वाले वर्षों में 20 रैंक सुधार के लिए रणनीति पर अमल करने का प्रयास होगा. रैंकिंग के लिए संकलन एवं प्रेषण में तीनों संकाय के डीन, डायरेक्टर , कुलसचिव के आलावा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ एमएस मल्लिक, डॉ बीके अग्रवाल व डॉ पीके सिंह का विशेष सहयोग रहा है. कुलपति ने इस सफलता के लिए सभी विश्वविद्यालय कर्मियों को बधाई दी है।

बोरी-बांध' से ग्रामीण कर रहे हैं अपने प्रयास से जलसंग्रह

सिदाम महतो

खूंटीः राज्य के खूंटी जिला में चल रहे जन शक्ति, जल शक्ति अभियान के तहत 'बोरी बांध' की चर्चा आज मीडिया में हो रही है। जिला के मुरहू प्रखंड के कई नाले में ग्रामीणों न मिलकर बोरी बांध का निर्माण किया। सेवा वेलफेयर सोसाइटी एवं जिला प्रशासन खूंटी ने ग्रामीणों के श्रमदान को उत्साहवर्धन कर ज्यादा से ज्यादा 'बोरी-बांध' निर्माण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

क्या है बोरी बांध?: बरसात का महीना खत्म होने के बाद नदी, नाला(सतिया) का जल -प्रवाह कम होने लगता है। गर्मी आते- आते तो नदी -नाला सूखने लगती हैं। जल संकट के संभावित खतरे को देखते हुए ग्रामीण नदी-नाले की धार को रेत या मिट्टी से मेड़ बनाकर रोककर रखते हैं। रेत या मिट्टी को बोरी में भरा जाता है इसलिए इसे 'बोरी बांध' कहा जा रहा है।अतिरिक्त जल की निकासी के लिए किनारे में एक निकास द्वार(पोईन) छोड़ दिया जाता है, ताकि बांध टूट न जाए।

जल संग्रह करने की यह तकनीक नई नही है। झारखंड में नदी , सतिया(नाला)किनारे के लोगों के लिए यह तकनीक वर्षों पुरानी है। पहले लोग बांध बनाने में बोरी का इस्तेमाल नही करते थे। नदी के किनारे के कई गांव वाले इस तरह का बांध बनाया करते थे। बैल, मवेशी की सहायता से रेत को इक्क्ठा कर मेड़ बना देते और अस्थाई बांध बना लेते थे।

ग्रामीणों के लिए यह बांध बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट हो जाता है

◆ मछली पालन- इस अस्थाई बांध में मछली पालन भी किया जाता है। जिस तरह मिलकर बांध का निर्माण करते है उसी तरह मिलकर मछलियों को मारते हैं और आपस मे बांट लेते हैं। आपस मे एकत्व का भाव निर्माण

होता है।◆गाय, बैल, मवेशी को नहलाने के लिए यह बांध काम मे आ जाता है। ◆ किनारे की जमीन पर फसल के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है। ◆ यह बांध गर्म पानी का स्रोत भी बन जाता है। बांध के मेड़ के नीचे से ठंड के महीने में गर्म जल का स्राव होता है और गर्मी के महीने में ठंड जल का स्राव होता है।

बांध के नीचे नहाने के लिए साफ और स्वच्छ पानी मिल जाता है। कोई लोग तो इस जोरक के पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं।ऐसे बांध के निर्माण से आसपास के कुओं में भी जलस्तर बढ़ जाता है। आपसी -एकता के अभाव में नदी किनारे के गांव के बहुत से ग्रामीण इस तकनीक को छोड़ चुके हैं। क्योंकि अकेले का काम नही है। यह एक टीम वर्क है।

खूंटी जिला प्रशासन और सेवा वेलफेयर सोसायटी की सक्रियता की वजह से नदी-नाला में अस्थाई बांध बांधने की हमारी पुरानी तकनीक फिर से जिंदा हो उठी है।इसी क्रम में ग्रामीणों के सहयोग के बल पर जिले के अंतिम छोर पर बसे मुरहू प्रखंड के रूमुतकेल पंचायत अंतर्गत बडा डाहंगा गांव के नाले पर दो और छोटा डाहंगा में तीन, कुल पांच बोरीबांध बनाये गए। उप विकास आयुक्त, अरूण कुमार सिह का कहना है कि जनशक्ति से जलशक्ति आंदोलन सराहनीय है। खूंटी के दुर्गम इलाके में पानी दुर्लभ होता जा रहा है। भूगर्भिय जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। ऐसे में पानी को बचाने के लिए सेवा वेलफेयर सोसाईटी और ग्रामीणों के द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से जल के लिए चलाया जा रहा यह आंदोलन सराहनीय है। डाहंगा में पूर्व से आदिवासियों द्वारा पत्थरों से की गई मेढ़बंदी, पत्थर और बोरियों से हुए बांध निर्माण से सीख लेने की बात उन्होंने कही।

मेकॉन ने वर्ष 2019-20 में 87.03 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज कर कीर्तिमान बनाया

संवाददाता

मेकॉन ने वित्त वर्ष 2019-20 में कर अदायगी से पूर्व 87.03 करोड़ रुपये का उल्लेखनीय लाभ दर्ज किया है और सात साल के उपरांत वित्त वर्ष 2012-13 के बाद पहली बार ऑपरेटिंग / परिचालन लाभ भी दर्ज किया है। इसके साथ साथ, मेकॉन ने अपने तीन मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों में 4929.87 करोड़ रुपये की अभूतपूर्व ऑर्डर बुकिंग के साथ एक नया मुकाम भी हासिल किया है।

संस्थान के प्रदर्शन के बारे में बोलते हुए, मेकॉन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अतुल भट्ट ने कहा कि ''मेकॉन ने कठिन समय को पार करके एक वापसी की है और अपने प्रगति पथ में उछाल लिया हैक उन्होंनें कहा कि मेकॉन ने एक सशक्त कॉर्पोरेट योजना का विकास किया है जो कि संस्थान की दक्षता और वर्तमान व्यावसायिक वातावरण पर आधारित है, जो निरंतर और लाभदायक विकास सुनिश्चित करता है।

मेकॉन की रणनीतिक योजना और समर्पित प्रयासों ने इस वित्त वर्ष के दौरान 647.51 करोड़ रुपये का राजस्व, जो कि संचालन से अर्जित है, के रूप में दर्ज करके इस वित्तीय वर्ष में कायाकल्प किया है, जो पिछले सात वित्तीय वर्ष (2012-13 से 2019-20) में सबसे अधिक है। इसके अलावा, इस वित्तीय वर्ष के लिए संस्थान का कुल मूल्य 433.49 करोड़ रुपये है, जो पिछले दस वित्त वर्ष (2010-11 से 2019-20) में सबसे अधिक है। इस-के फलस्वरूप, मेकॉन वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार को 21.67 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान करने का प्रस्ताव कर रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए संस्थान के प्रति कर्मचारी आय में भी पिछले वर्ष की तुलना में 40.54% का सुधार हुआ है।

अतुल भट्ट ने कहा कि मेटल्स एवं माइनिंग क्षेत्र संस्थान का मुख्य आधार हमेशा से रहा है, लेकिन मेकॉन ने ऊर्जा और इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्य विविध क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बढ़ाने के लिए ठोस उपाय किए हैं एवं राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं और भारत सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए मजबूत कदम उठाये हैं, ताकि राजस्व में वृद्धि हो सके , पदचिह्नों का विस्तार किया जा सके और चक्रीयता की नकारात्मकता से व्यापार को बचाया जा सके ।

रोजगार

रोजगार के लिए मत्स्य बीज उत्पादन

आशीष कुमार

तालाबों में मछली उत्पादन में जैसे-जैसे वृद्धि हो रही है वैसे-वैसे मछली के बीज का मांग भी बढ़ रहा है। देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा जिला का राम सागर ग्राम और कोलकाता के निकट नैहाटी मत्स्य बीज के प्रमुख केंद्र रहे हैं। बहुत सारे किसान भाइयों को मछली बीज की उपलब्धता को लेकर भी समस्यायें आती रहती हैं। कई तो इसकी उपलब्धता में समस्याओं के कारण मछली पालन को एक मुश्किल पेशा समझते हैं। परंतु यदि प्रयास किया जाए तो अन्य क्षेत्रों में भी बीज उत्पादन किया जा सकता है। मछली पालन के लिए बीज की आवश्यकता बनी रहती है। कभी-कभी तो समय पर बीज नहीं मिलने के कारण कई किसान मछली पालन नहीं कर पाते है। इस प्रकार मछली के बीज का उत्पादन के क्षेत्र में बहुत बड़ा अवसर है जिसका लाभ छोटे तालाबों के मालिक ले सकते हैं। सरकार के द्वारा मत्स्य बीज उत्पादन के लिए प्रशिक्षण तथा अनुदान पर मत्स्य अंड बीज या स्पान भी उपलब्ध कराया जाता है। यह एक मौसमी कार्य है जिसमें मात्र 3 माह का समय लगता है और अच्छी कमाई हो सकती है।

देखा जाए तो एक लाख स्पॉन से 25000 बीज का उत्पादन किया जा सकता है परंतु यदि ध्यान देकर मेहनत किया जाए तो 60 से 70000 तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही एक ही तालाब में इस कार्य को तीन बार किया जा सकता है। इसके लिए तालाबों के मालिक उपयुक्त ग्राहक हैं और यदि बीज से मछली का उत्पादन संतोषजनक हुआ तो अगले वर्ष भी बीज की मांग बनी रहेगी।

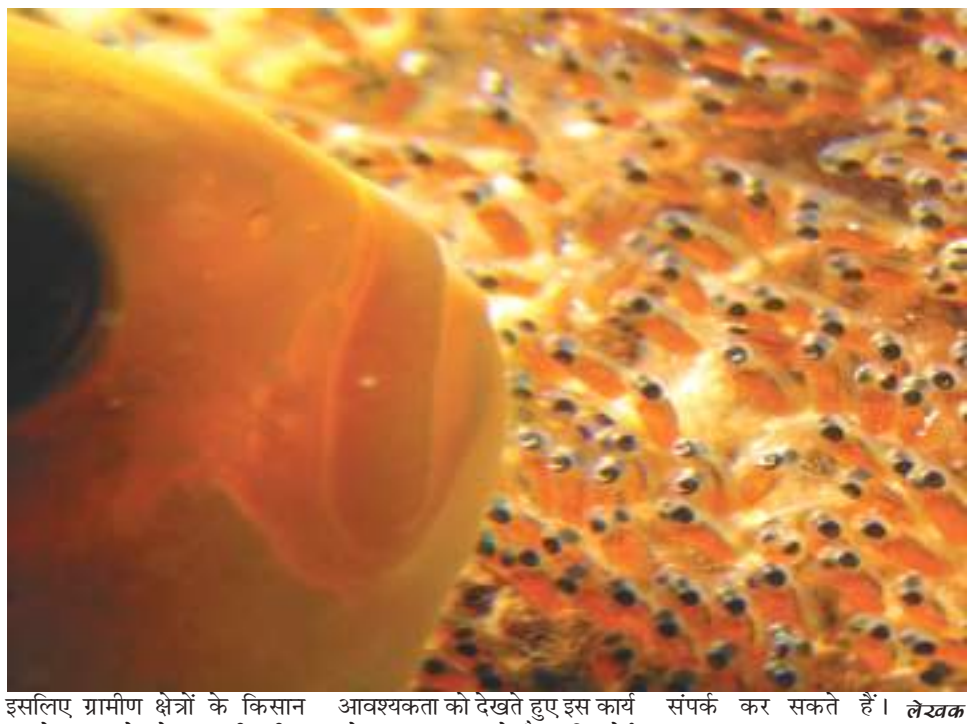

इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के किसान अपने तालाबों में मछली बीज उत्पादन के अवसर को पहचान कर और स्थानीय स्तर पर बीज की आवश्यकता को देखते हुए इस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। यदि कोई कठिनाई हो तो अपने जिले के मत्स्य पदाधिकारी अथवा सीधे लेखक से संपर्क कर सकते हैं। *लेखक सेवानिवृत उपनिदेशक (मत्स्य विभाग) हैं* Ph. 9430783037 email:coomar2012@gmail.com

किसानों को भी वार्ता में रचनात्मक होना होगा

किसान आंदोलन के वार्ता के माध्यम से किसी अंजाम तक पहुंचने की उम्मीद क्षीण सी दिख रही है। किसान नेता अपने जिद पर अड़े हुये हैं। इस बीच किसान आंदोलन के कर्ता धर्ता नेताओं ने आठ दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद में विपक्ष का भी पूरा समर्थन रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर लचीला रूख अपनाने के संकेत दे रही है, पर किसान नेताओं का कहना है कि हम तीनों कानून को वापस लेने से कम किसी और बात पर नहीं मानेंगे। यानि यह आंदोलन एक जिद की तरह है कि सरकार कानून को रद्द करे। ऐसी स्थिति में बातचीत का कोई औचित्य नहीं रह जाता। क्योंकि सरकार ने भी यह कह दिया है कि कानून को वापस नहीं लेंगे।

देश में किसानों को नीरीह, शोषित और सीधा सादा माना जाता है, लेकिन वर्तमान कृषि कानूनों पर उनका रूख जिद्दी की तरह उभर कर सामने आया है। केंद्र सरकार ने वार्ता से पहले ही कहा था कि हम किसानों के सभी आपत्तियों पर विचार कर उसका निराकरण करने को तैयार हैं और कानून में समुचित बदलाव भी करेंगे। बावजूद इसके आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं की जिद और दिल्ली समेत देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी इस आंदोलन को किसी निष्कर्ष से दूर ले जा रही है। ऐसे में जो आंदोलन अभी दिल्ली के आस पास हो रहे हैं वह संभव है देशव्यापी होगा और एक अराजक स्थिति ही बनेगी।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कोई भी केंद्र सरकार किसानों के अहित का कोई कानून लाने से बचना चाहेगी। साथ ही यह भी सच है कि कृषि प्रधान देश में आज नौ हजार लोग रोज खेती बारी छोड़ कर शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। स्पष्ट है कि हमारी कृषि नीतियां आजादी के बाद से किसानों के हित में नहीं रही हैं। भले हम उसे किताबों और भाषणों में अन्नदाता कह कर सम्मान देते हैं लेकिन देश का किसान आज भी संघर्षरत है।

किसानों की इस स्थिति को सुधारने के मकसद से ही केंद्र सरकार ने कृषि नीतियों में बड़े बदलाव के कदम उठाये हैं। इसमें संभव है त्रूटियां और कमियां भी होंगी जिसे मिल बैठ कर इसका आकलन कर सुधारा भी जा सकता है। लेकिन सीधे इसका मुखर विरोध और इन कानूनों को वापस लेने की मांग किसानों के लिये किसी भी तरह से सही नहीं होगा। हमारी पुरानी कृषि नीतियों में अवश्य खामियां रही होंगी तभी देश का किसान बुरी स्थिति में है। आंदोलनकारियों को वार्ता में रचनात्मक होना ही होगा।

सालाना 6 फ़ीसद जीवाश्म ईंधन उत्पादन घटाना होगा

जहाँ एक ओर दुनिया में कोविड की आर्थिक मार से उबरने के लिए तमाम देश जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने वाले क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर दुनिया के प्रमुख अनुसंधान संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से बनी प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के एक विशेष अंक में यह पाया गया है कि अगर हमें दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग की जानलेवा मार से बचाना है तो तमाम देशों को अपने जीवाश्म ईंधन उत्पादन पर लगाम लगानी होगी। ऐसी लगाम कि उत्पादन हर साल 6 प्रतिशत की दर से घटे। लेकिन फ़िलहाल तमाम देश जीवाश्म ईंधन उत्पादन में सामूहिक 2% वार्षिक वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं।

रिपोर्ट की मानें तो क्योंकि कोविड-19 से रिकवरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण और नया मोड़ है, इसलिए देशों को अधिक कोयले, तेल और गैस उत्पादन के स्तर में बंध जाने से बचने के लिए अपनी राह बदलना चाहिए जिससे 1.5 ट उ की सीमा तक वैश्विक तापमान को बढ़ने से रोका जा सके। पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने और 1.5 °C मार्ग के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए, देशों को आने वाले दशक में सामूहिक रूप से जीवाश्म ईंधन के उत्पादन में 6% सालाना की गिरावट की आवश्यकता होगी। सऊदी अरब, रूस और अमेरिका जैसे प्रमुख निर्यातकों को उत्पादन को और भी तेज दर से कम करने की आवश्यकता होगी। लेकिन इसके बजाय, देश जीवाश्म ईंधन उत्पादन में सामूहिक 2% वार्षिक वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, कई क्षेत्रों की तरह, कोविड-19 से तेल और गैस भी काफी प्रभावित हुए हैं, और प्रारंभिक अनुमान में जीवाश्म ईंधन का उत्पादन वर्ष पर 7% तक गिर गया है। लेकिन जब तक देश और उद्योग के खिलाड़ी अपने तरीके नहीं बदलते, उत्पादन में गिरावट सिर्फ अस्थायी होने की संभावना है। जीवाश्म ईंधन उत्पादकों और सरकारों को एक मौलिक विकल्प का सामना कर रहें है - एक ग्रीन (हरी) वसूली का चुनाव करने या एक पूर्व-कोविद समर्थक जीवाश्म ईंधन प्रक्षेपवक्र में वापस आने के बीच - जिसमें से उत्तर-ार्द्ध गंभीर जलवायु व्यवधान को लॉक इन कर देगा। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अन्य प्रमुख शोधकर्ताओं द्वारा लिखित उत्पादन गैप रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष हैं; स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान, क्क्रऊ प्रवासी विकास संस्थान, जलवायु विश्लेषिकी और CICERO। 2020 के प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के अनुसार, देशों ने अगले दशक में अपने जीवाश्म ईंधन उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनाई है बावजूद इसके कि अनुसंधान से पता चलता है कि वैश्विक वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए दुनिया को प्रति वर्ष 6% उत्पादन में कमी करने की आवश्यकता है। पहली बार 2019 में जारी की गयी यह रिपोर्ट, पेरिस समझौते के लक्ष्यों और कोयला, तेल और गैस के नियोजित उत्पादन के बीच अंतर को मापती है। यह पता करती है कि "उत्पादन अंतर" (प्रोडक्शन गैप) अभी भी बहुत बड़ा बना हुआ है: 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा के अनुरूप होने के बजाय देशों की योजना 2030 में जीवाश्म ईंधन की अनुरूप सीमा की तुलना में दोगुनी से अधिक उत्पादन की योजना है।

इस वर्ष का विशेष अंक कोविड-19 महामारी के निहितार्थ और कोयले, तेल और गैस उत्पादन पर सरकारों के प्रोत्साहन और रिकवरी के उपायों को देखता है। यह एक संभावित नए मोड़ पर आता है, क्योंकि महामारी अभूतपूर्व सरकारी कार्रवाई का संकेत देती है - और चीन, जापान और दक्षिण कोरिया सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं नेट -ज़ीरो उत्सर्जन तक पहुंचने का वादा किया है।

इस साल की विनाशकारी जंगल की आग, बाढ़, और सूखा और अन्य अजीब मौसम की घटनाओं एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करतीं हैं कि हमें किस कारण जलवायु संकट से निपटने में सफल होना चाहिए। जैसा कि हम कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्थाओं को दुबारा बनाना चाहते हैं, निम्न-कार्बन ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में निवेश करना नौकरियों के लिए, अर्थव्यवस्थाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए और स्वच्छ हवा के लिए अच्छा होगा। सरकारों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं और ऊर्जा प्रणालियों को जीवाश्म ईंधन से दूर करने का अवसर हथियाना चाहिए, और अधिक न्यायसंगत, टिकाऊ और लचीला भविष्य की दिशा में बेहतर निर्माण करना चाहिए," इंगर एंडरसन, कार्यकारी निदेशक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने कहा।

स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्ट- और UNEP द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई। कई विश्वविद्यालयों और अतिरिक्त शोध संगठनों में फैले हुए दर्जनों शोधकर्ताओं ने विश्लेषण और समीक्षा में योगदान दिया। "अगर हम देश में मौजूदा स्तर पर जीवाश्म ईंधन का उत्पादन जारी रखते हैं, तो अनुसंधान में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति है कि हमें गंभीर जलवायु व्यवधान का सामना करना पड़ेगा। अनुसंधान समाधान पर समान रूप से स्पष्ट है: सरकारी नीतियां जो जीवाश्म ईंधन के लिए मांग और आपूर्ति दोनों को कम करती हैं और वर्तमान में उन पर निर्भर समुदायों का समर्थन करती हैं। यह रिपोर्ट उन कदमों की पेशकश करती है जो सरकारें जीवाश्म ईंधन से दूर निष्पक्ष और न्यायसंगत संक्रमण के लिए आज ले सकती हैं,'' माइकल लाज़ारस, रिपोर्ट के मुख्य लेखक और रएक (एसईआई) के वर (यूएस) सेंटर के निदेशक, ने कहा।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष कुछ इस प्रकार हैं

- 1.5 °C-सुसंगत मार्ग का अनुसरण करने के लिए दुनिया को 2020 और 2030 के बीच जीवाश्म ईंधन के उत्पादन में लगभग 6% प्रति वर्ष की कमी करनी होगी। इसके बजाय देश 2% की औसत वार्षिक वृद्धि का इरादा और मंसूबा बना रहे हैं और इसका नतीजा 2030 तक उत्पादन में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के संरेखित से दोगुना से अधिक उत्पादन होगा।
- 2020 और 2030 के बीच, 1.5% उ मार्ग के अनुरूप होने के लिए सालाना वैश्विक कोयला, तेल और गैस उत्पादन में क्रमशः 11%, 4% और 3% की गिरावट होनी पड़ेगी।
- कोविड-19 महामारी - और इसके प्रसार को रोकने के लिए "लॉकडाउन" उपाय से - 2020 में कोयला, तेल और गैस उत्पादन में थोड़े समय के लिए गिरावट आई है। लेकिन पूर्व-कोविड योजनाएं और कोविड के बाद के स्टिम्युलस उपाय बढ़ती वैश्विक जीवाश्म ईंधन प्रोडक्शन गैप (उत्पादन अंतर) की निरंतरता का संकेत देतें हैं, जिससे गंभीर जलवायु व्यवधान का जोखिम है।
- आज तक, ˘20 सरकारों ने जीवाश्म ईंधन उत्पादन और खपत के लिए जिम्मेदार सेक्टरों को कोविड-19 उपायों में 230 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की लागत दी है, जो कि स्वच्छ ऊर्जा से कहीं अधिक है। जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नीति निर्माताओं को इस प्रवृत्ति को उलट देना चाहिए।

''महामारी से प्रेरित डिमांड शॉक (मांगों की दहशत) और इस साल तेल की कीमतों में गिरावट ने एक बार फिर कई जीवाश्म ईंधन-निर्भर क्षेत्रों और समुदायों की भेद्यता को दर्शाया है। इस जाल से निकलने का एकमात्र तरीका जीवाश्म ईंधन से परे इन अर्थव्यवस्थाओं का विविधीकरण है। यह दुखद बात है कि 2020 में हमने कई सरकारों को जीवाश्म ईंधन और इन कमजोरियों को और ज़्यादा बढ़ाते देखा। इसके बजाय, सरकारों को आर्थिक विविधीकरण और स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक ऐसे परिवर्तन को निर्देशित करना चाहिए जो बेहतर दीर्घकालिक आर्थिक और रोजगार क्षमता प्रदान करता है। यह 21-वीं सदी के सबसे चुनौतीपूर्ण उपक्रमों में से एक हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक और प्राप्त करने योग्य है।

ब्राज़ील में बह रही उल्टी गंगा

क्लाइमेट कहानी

वर्षा वनों की कटाई ऊपर, पर्यावरण संरक्षण बजट नीचे

भले ही ब्राज़ील में अमेज़न वर्षावनों की कटाई 2008 के बाद से उच्चतम स्तर पर हो, लेकिन वहां के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को शायद इसकी परवाह नहीं। उन्होंने तो ब्राज़ील कांग्रेस को एक ड्राफ्ट बजट बिल भेजा है, जिसे यदि अनुमोदन मिल जाता है, तो वह इस कटाई के ख़िलाफ़ किसी भी कानून प्रवर्तन पहल की अनुमति नहीं देगा। और ये तब है जब ब्राज़ील दुनिया का 5-वां सबसे बड़ा GH (जीएचजी) एमिटर (उत्सर्जक) है। ख़ास बात ये है कि अन्य शीर्ष उत्सर्जकों के विपरीत, ब्राज़ील का उत्सर्जन मुख्य रूप से वनों की कटाई, कृषि और मवेशियों से होता है। ब्राजील के गैर सरकारी संगठनों के अनुसार, यदि सरकार के इस बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है, तो देश में वनों की कटाई और जल से लड़ने के लिए कोई वित्तीय संसाधन नहीं होंगे।

अमेज़ॅन वनों की कटाई अगस्त 2019 और जुलाई 2020 के बीच 9.5% बढ़ गई और पिछले 12 महीनों में 10,129 किमीः की तुलना में 11,088 किमीः तक पहुंच गई। यह अवक्‍मित क्षेत्र 12 वर्षों में सबसे बड़ा है और साओ पाउलो शहर के आकार के 7.2 गुना के बराबर है। यह ब्राज़ील की ढफ्ढञ्र नामक वन कटाई निगरानी प्रणाली के आँकड़े हैं और वहां की राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (क्ठढए) के अनुसार 95% तक सही हैं।

आंकड़ों की इस घोषणा के दौरान ब्राज़ील के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालय मंत्री मार्कोस पोंटेस और उपराष्ट्रपति जनरल हैमिल्टन मौराओ, जो नेशनल काउंसिल ऑफ़ लीगल अमज़ोनिया की अध्यक्षता करते हैं, उपस्थित थे। मौराओ ने वनों की कटाई को रोकने के लिए किसी भी उपाय की घोषणा नहीं की और कहा कि डिग्रेडेशन (नाश) और अधिक हो सकता है। हाल के वर्षों में यह पहली बार था कि पर्यावरण मंत्री अनावरण समारोह में उपस्थित नहीं थे, जिस पद को रिकार्डो साल्लेज़ ने निभाया।

इस बीच, नए प्रस्तुत बिल के जवाब में, ग्रीनपीस ब्राज़ील सहित 23 सिविल सोसाइटी संस्थानों ने सांसदों के बिल को बदलने की मांग करने के लिए "वन विद नो कट्स" अभियान शुरू कर दिया। आन्दोलन की अब वजह और भी साफ़ है क्योंकि क्योंकि मौजूदा सरकार द्वारा अपनी पर्यावरण-विरोधी नीति के अंतर्गत ब्राजील में पर्यावरण संरक्षण को कम करने के लिए पर्यावरण के लिए उपलब्ध बजट में कमी कर देना और संसाधनों को खर्च न करना दो तरीके हैं अपना मक़सद पूरा करने के। बजट में हुई कमी पर नज़र डालें तो साल 2019 से 2020 तक, पर्यावरण प्रहरी इदामा के विवेकाधीन खर्च बजट में 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर (30.4%) की कमी आई; क्ळट-इड्ड (संरक्षण इकाइयों की निगरानी करने वाली एजेंसी) के लिए वर $ 18 मिलियन (32.7%) की कमी, और पर्यावरण मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासन के लिए वर $ 6 मिलियन (32.7%) की कमी आयी। इस ताज़ा घटनाक्रम पर ग्रीनपीस ब्राज़ील के अमेज़ॅन अभियान की प्रवक्ता क्रिस्टियन मेज़ेट्टी कहती हैं, "सरकार की यह नीतियां यह जलवायु, जैव विविधता और ब्राजील के समाज के लिए अकल्पनीय क्षति पैदा कर रही है। कांग्रेस को कहिये कि इस संदर्भ में वो सरकार के आर्थिक संसाधनों का हिस्सा Ibama और ICMBio जैसी संस्था को हस्तांतरित कर सकती है, क्योंकि उनके पास वनों की कटाई और आग से लड़ने के लिए कानूनी क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता है।

आगे ब्राज़ील के जलवायु वेधशाला (क्लाइमेट ऑब्ज़रवेटोरी) के कार्यकारी सचिव मारासिओ अस्ट्रिनी कहते हैं, ''आमतौर पर, जब वनों की कटाई बढ़ती है, तो हम यह सोचकर हैरान रह जाते हैं कि पर्यावरण अपराध को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयासों में क्या गलत हुआ। इस बार, हम जानते हैं कि वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि सरकार का इरादा था और अंततः, ब्राज़ील सरकार द्वारा पर्यावरण बजट को घटाने की कवायद पर Climate Observatory में नीति विशेषज्ञ सुलेय अरुजो कहते हैं, "पर्यावरण एजेंसियों के लिए 2021 के लिए कम बजट का प्रस्ताव यह स्पष्ट करता है कि सरकार इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं देती है। एक ओर तो उपराष्ट्रपति वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए मजबूत कार्रवाई का वादा करते हैं और दूसरी ओर ऐसा बिल प्रस्तुत हो रहा है।

तापमान एवं गर्मी

जनवरी से अक्टूबर 2020 के बीच वैश्विक माध्य तापमान 1850-1920 बेसलाइन से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। इसे प्री इंडस्ट्रियल स्तरों के सन्निकटन (एप्रोक्सीमेशन) के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इस बात की आशंका काफी ज्यादा है कि वर्ष 2020 वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड किए गए अब तक के सबसे गर्म तीन सालों में शामिल हो जाएगा। तापमान दर्ज करने का आधुनिक काम वर्ष 1850 में शुरू हुआ था।

डब्ल्यूएचओ के आकलन पांच वैश्विक तापमान डाटा सेट्स पर आधारित हैं। यह सभी डेटा सेट इस वक्त वर्ष 2020 को अब तक के दूसरे सबसे गर्म साल के तौर पर सामने रखते हैं। वर्ष 2016 अब तक का सबसे गर्म साल रहा था जबकि 2019 तीसरे सबसे गर्म साल के तौर पर दर्ज किया गया है। इन तीन सबसे गर्म सालों के बीच तापमान का फर्क बहुत थोड़ा है। हालांकि जब समूचे साल का डाटा उपलब्ध होगा तब हर डाटा सेट की सटीक रैंकिंग में बदलाव हो सकता है। सबसे ज्यादा गर्माहट उत्तरी एशिया, खासतौर पर साइबेरियन आर्कटिक में दर्ज की गई, जहां तापमान औसत के मुकाबले पांच डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा चढ़ गया। साइबेरिया में गर्मी का चरम जून के अंत में हुआ जब वेर्खोयांस्क का तापमान 20 जून को 38 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह अनंतिम रूप से आर्कटिक सर्किल के उत्तरी इलाकों में किसी भी स्थान पर दर्ज किया गया सबसे ज्यादा तापमान था। यह पिछले 18 साल के डेटा रिकॉर्ड में जंगलों में आग लगने की सबसे सक्रिय परिघटना के लिए ईंधन साबित हुआ।

पर्यावरण संकट उत्पन्न करने पर 33 देशों को कोर्ट नोटिस

पुर्तगाल के छह युवाओं ने ग्लोबल लीगल एक्शन नेटवर्क के सहयोग से दायर की थी याचिका, यूरोप के मानवाधिकार न्यायालय ने मांगा इन देशों से जवाब

पर्यावरण के प्रति चिंता अब बढ़ने लगी है। इसके संरक्षण को लेकर जागरूकता भी फैल रही है। यह जन जागरूकता का ही नतीजा है कि यूरोप के मानवाधिकार न्यायालय ने 33 देशों के खिलाफ पर्यावरण संबंधी मामले में संज्ञान लेते हुए उनसे जवाब मांगा है। यह शायद विश्व में पहली ऐसी कानूनी कार्यवाही होगी, जहां न्यायालय ने ऐसा संज्ञान लिया है। इस मामले में पुर्तगाल के छह युवा याचिकाकर्ता शामिल हैं। सामान्यतया इस प्रकार के मामलों में कड़ा संज्ञान कम ही मामलों में लिया जाता है। अहम बात यह कि युवाओं ने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता जताई तो न्यायालय ने भी उसे गंभीरता से लिया और एक साथ इतने देशों को नोटिस जारी किया। पुर्तगाल के इन छह युवाओं ने याचिका में आरोप लगाया है कि 33 देशों द्वारा पर्यावरण के लिए संकट पैदा किया गया है। मालूम हो कि यह याचिका ग्लोबल लीगल एक्शन नेटवर्क के सहयोग से दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पर्यावरण असंतुलन का सीधा प्रभाव ऊनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। न्यायालय ने इस आरोप का संज्ञान लेते हुए पूछा है कि क्या युवा याचिकाकर्ताओं के मानव अधिकार का हनन हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय ने माना है कि पर्यावरण संकट के कारण पुर्तगाल के युवाओं के मानवाधिकार का हनन हो रहा है। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इन युवाओं के वकील गैरी लिस्टन ने कहा, ''ये बहादुर युवा एक बड़ी बाधा पार कर चुके हैं। यह निर्णय यूरोपीय सरकारों को उनके जलवायु शमन प्रयासों में तेजी लाने के लिए मजबूर करता है। बड़ी बात यह है कि यह फ़ैसला यूरोपीय संघ के 2030 उत्सर्जन लक्ष्य के फैसले से कुछ हफ्ते पहले ही आता है। ध्यान रहे कि 2030 तक 65% की कमी से कम कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा।''

आर्कटिक में तेजी से पिघलता समुद्री बर्फ

1980 के दशक के मध्य से कम से कम 2 बार ऐसा हुआ है जब आर्कटिक महासागर के तापमान में वैश्विक औसत के बराबर तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से गर्मियों में आर्कटिक सागर पर जमी बर्फ की परत के पिघलने का लंबा दौर चला। इसका मध्य अक्षांश वाले क्षेत्रों की जलवायु पर असर पड़ा।

आर्कटिक सागर पर जमी बर्फ सितंबर माह में अपने सालाना न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। यह 42 साल पुराने सेटेलाइट रिकॉर्ड में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट थी। जुलाई और अक्टूबर 2020 में आर्कटिक सागर पर जमी बर्फ का क्षेत्र अब तक के न्यूनतम स्तर के रूप में दर्ज हो चुका है।

लैपटेक सागर पर जमी बर्फ वसंत, गर्मी और सर्दी के मौसम में अभूतपूर्व रूप से कम रही। जुलाई और अक्टूबर 2020 के बीच नॉर्दन सी रूट या तो बर्फ से बिल्कुल मुक्त था या फिर खत्म होने की कगार पर था।

नर्म कोयले के मैदानों यानि पीटलैंड्स की बर्बादी रोकना ज़रूरी: वैज्ञानिक

एजेंसियां

सरल शब्दों में कहें तो पीट्लैंड दरअसल नर्म कोयले, या पीट. के मैदान होते हैं। पीट बहुत कारणों से हमारे ग्रह के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह न सिर्फ़ एक कार्बन स्टोर के रूप में कार्य करता है, पीट्लैंड वन्यजीवों के लिए एक बेहतरीन रिहाइश का किरदार भी हैं। जल प्रबंधन में भी इसकी भूमिका है, और यहाँ तक की पुरातात्विक नजर से भी ये बढ़िया है क्योंकि इसमें चीजों को संरक्षित करने की क्षमता होती है।

शोधकर्ताओं ने एक ताज़ा शोध के आधार पर कहा है कि दुनिया के पीटलैंड्स - और उनमे बसे विशाल कार्बन भंडार - का संरक्षण जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेटर विश्वविद्यालय और टेक्सास अ&ट (ए एंड एम) विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किया गया यह अध्ययन, मानव इतिहास में पीटलैंड के नुकसान की जांच करता है और भविष्य में ये "प्रवर्धित" होगा यह अंदाजा लगता है।

पीटलैंड्स को इस सदी में एक समग्र "सिंक" (कार्बन को अवशोषित करने) से एक स्रोत में स्थानांतरित होने की उम्मीद है, मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय (ट्रॉपिक्स) में मानव प्रभावों की वजह से, और अध्ययन ने चेतावनी दी कि 2100 तक 100 बिलियन टन से अधिक कार्बन जारी हो सकता है, हालांकि संदेह अब भी बरक़रार हैं। पीटलैंड्स को वर्तमान में जलवायु परिवर्तन अनुमानों के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य अर्त सिस्टम मॉडल से बाहर रखा गया है - शोधकर्ताओं का कहना है कि इस बात को तत्काल ठीक किया जाना चाहिए।

एक्सेटर के ग्लोबल सिस्टम इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर एंजेला गैलेगो-साला ने कहा, "पीटलैंड में दुनिया के सभी जंगलों की तुलना में अधिक कार्बन है और कई जंगलों की तरह उनका भविष्य अनिश्चित है। पीटलैंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं, जैसे कि जंगल की आग और सूखे का खतरा, पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना और बढ़ते समुद्री स्तर।'' वो आगे कहते हैं, "पीटलैंड के लिए मुख्य खतरे अधिक प्रत्यक्ष हैं - विशेष रूप से मनुष्यों द्वारा कृषि भूमि बनाने के लिए उसका विनाश। इसका मतलब पीटलैंड्स का भविष्य निश्चित रूप से हमारे हाथ में है।"

पीटलैंड्स पृथ्वी पर लगभग हर देश में पाई जाने वाली एक प्रकार की आर्द्रभूमि (वेटलैंड) है, जो वर्तमान में वैश्विक भूमि की सतह का 3% है। प्रोफेसर गैलेगो-साला का कहना है कि पीटलैंड्स को कुछ जलवायु मॉडल्स में "अनदेखा" किया गया है क्योंकि उन्हें "निष्क्रिय" के रूप में देखा जाता है - जो अपने आप छोड़े जाने पर ना तो तीव्र गति से कार्बन अवशोषित करते हैं और ना ही कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। मॉडल से यह बहिष्करण भविष्य के परिवर्तनों का अनुमान लगाना मुश्किल बनाता है, इसलिए अध्ययन ने 44 अग्रणी पीटलैंड विशेषज्ञों के सर्वेक्षण के अनुमानों के साथ मौजूदा शोध को संयुक्त किया है। इसके आधार पर, यह 2020-2100 तक 104 बिलियन टन पर कुल कार्बन नुकसान का अनुमान लगाता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि यह अनुमान बहुत अनिश्चित है (103 बिलियन टन के लाभ पर 360 बिलियन टन तक का नुकसान) - लेकिन यह मॉडल में समावेश की आवश्यकता और बेहतर पीटलैंड संरक्षण की आवश्यकता, दोनों को दर्शाता है। "हालांकि हम अधिक जानकारी चाहते हैं, हमें स्पष्ट रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हम इन पारिस्थितिक तंत्रों का प्रबंधन कैसे करते हैं," डॉ। गैलेगो-साला ने कहा। वो कहते हैं, "हम पीटलैंड्स के धुएं में फुंक जाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं।

अमेज़ॅन और कांगो में उष्णकटिबंधीय (ट्रॉपिक्स) पीटलैंड की नई "खोजें" मुख्य रूप से बरक़रार हैं, और शोधकर्ताओं का कहना है कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास ठोस नीतियां हों।

"हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसा रास्ता निकालें जो लोगों और धरती के लिए का समर्थन करें," डॉ. गैलेगो-साला ने कहा। "जहां लोगों के पास पीटलैंड को नष्ट करने के लिए मजबूत आर्थिक प्रोत्साहन है- या यहां तक कि ज़रूरत है - हमें ऐसी योजनाओं और नीतियों की आवश्यकता है जो अधिक टिकाऊ विकल्प प्रदान करतीं हैं।"

यह शोध पेपर नेचर क्लाइमेट चेंज नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है, जिसका शीर्षक: "वैश्विक पीटलैंड कार्बन सिंक की भविष्य की भेद्यता का विशेषज्ञ आकलन" है। इस अंतर्राष्ट्रीय शोध दल में हेलसिंकी और क्यूबेक विश्वविद्यालय शामिल थे। और इसके फंडर्स में पास्ट ग्लोबल चेंजेस प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर क्वाटरनरी रिसर्च (INQUA) और नेचुरल एनवायरमेंट रिसर्च काउंसिल (NERC) शामिल थे।

सीसीएल में सेवानिवृत कर्मियों को दी भावभीनी विदाई

रांची : कोरोना वैश्विक महामारी के कारण ''सम्मान समारोह''का कार्यक्रम सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (सीसीएल) में स्थगित था। कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुये जून, जुलाई, अगस्त एवं नवम्बर माह में सेवानिवृत हुये कर्मियों को सीसीएल मुख्यालय, रांची के ''

कन्वेंशन सेन्टर'' में'सम्मान समारोह' का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया गया। नवम्बर, 2020 में 141 कर्मचारी सेवानिवृत हुये हैं।

सदी के अंत तक 3 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगी तापमान में हो रही वृद्धि

यूएन द्वारा प्रकाशित "एमिशन गैप रिपोर्ट 2020" से पता चला है कि यदि तापमान में हो रही वृद्धि इसी तरह जारी रहती है, तो सदी के अंत तक यह वृद्धि 3.2 डिग्री सेल्सियस के पार चली जाएगी। जिसके विनाशकारी परिणाम झेलने होंगे। तापमान में आ रही इस वृद्धि का सीधा असर आम लोगों के जनजीवन पर भी पड़ेगा। बाढ़, सूखा, तूफान जैसी आपद-ाओं का आना आम बात हो जाएगा। जिसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ेगा। जहां एक तरफ यह आपदाएं उनके जीवन पर असर डालेंगी वहीं दूसरी तरफ यह कृषि पर भी असर करेंगी जिसका असर आर्थिक क्षेत्र पर भी पड़ेगा। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 और उसके कारण आए ठहराव के चलते उत्सर्जन में कुछ कमी आई थी पर वो कमी लम्बे समय तक नहीं रहेगी।

रिपोर्ट का मानना है कि महामारी से आई आर्थिक मंदी के चलते 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में करीब 7 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है। हालांकि यह कमी पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने में कोई ज्यादा मदद नहीं करेगी। अनुमान है कि 2020 में उत्सर्जन में जो कमी आई है, उसके चलते 2050 तक तापमान में सिर्फ 0.01 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। ऐसे में यदि महामारी का फायदा उठाना है तो इस आर्थिक मंदी से उबरते वक्त पर्यावरण और क्लाइमेट को भी ध्यान में रखना होगा।

शहद में मिलावट के काले कारोबार का खुलासा

सीएसई की सबसे बड़ी पड़ताल: शहद के लगभग सभी ब्रांड में बड़े पैमाने पर मिलाई जा रही है चीनी

शहद एक ऐसा तत्व है जिसमें दुनियाभर में मिलावट होती है। खाद्य उत्पादन से जुड़े लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। यह बात भी सब जानते हैं कि जब भी नियामक मिलावट के कारणों का पता लगाने के करीब पहुंचते हैं, तो मिलावट के नए रास्ते खोज लिए जाते हैं। शहद की धोखाधड़ी एक उम्दा उद्यम बन चुका है। हनीगेट की कहानी विश्वव्यापी है ।

यह कहानी उत्तर भारत में सरसों के खेतों से शुरू होती है जहां मधुमक्खी पालक शहद के अगले मौसम की तैयारी कर रहे हैं। सरसों के खेतों में जब फूल आते हैं, तब मधुमक्खी मकरंद चूसकर उसे शहद के रूप में हमें देती है। इस शहद का उपयोग करके हमें बहुत से फायदे मिलते हैं। हमें खबर मिली थी इस क्षेत्र और अन्य इलाकों के मधुमक्खी पालक गहरे संकट में हैं। पिछले कुछ सालों में शहद के भाव लगातार गिरने से हालात इतने बुरे हो गए हैं कि वे अपना कारोबार छोड़ने की स्थिति में पहुंच गए हैं। शहद का कारोबार अब उनके लिए फायदे का सौदा नहीं रह गया है। कच्ची शहद के भाव में ऐसी गिरावट पहले कभी नहीं देखी गई। भाव आखिर क्यों गिर रहे हैं? वह भी ऐसे समय में जब शहद की बिक्री लगातार बढ़ रही है और कोविड-19 के संक्रमण के खतरे के बीच अधिक से अधिक लोग एंटी मा-इक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण इसका अधिक सेवन कर रहे हैं। ऐसे समय में जब एक गिलास पानी में शहद मिलाकर नीबू के साथ पीना लाखों परिवारों के बीच सामान्य हो गया है, तब शहद का भाव गिरना चौंकाता है। इसके अलावा हम यह भी जानते हैं कि केंद्र सरकार मधुमक्खी पालकों के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है। उनके जीवनयापन और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ऐसे समय में इस पेशे से मोहभंग की आखिर क्या वजह हो सकती है?

जब इन राज्यों में तथ्यों की पड़ताल की गयी मधुमक्खी पालकों की दुखभरी कहानियां सुनने को मिलीं। एक के बाद एक मधुमक्खी पालक ने यही कहा, ''2014-15 तक हमें शहद का अच्छा मूल्य मिल रहा था। इसके बाद गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। शहद का भाव पहले 150 रुपए प्रति किलो था। अब यह 60-70 रुपए के करीब पहुंच गया है।'' राजस्थान के भरतपुर जिले में कच्ची शहद का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। यहां के मधुमक्खी पालक राम गोपाल बताते हैं, ''मैंने मधुमक्खी के बॉक्स दोगुने कर दिए हैं, लेकिन वर्तमान में आमदनी पांच साल पहले से भी कम है। अब मैं यह काम छोड़ने की सोच रहा हूं।'' उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गंगो गांव के अमरनाथ भंवर सिंह कहते हैं, ''फायदा कम होने पर मैंने मधुमक्खी पालन का काम छोड़ दिया है।'' उत्तर प्रदेश के रामपुर में मधुमक्खी पालक और व्यापारी संजय नेगी बताते हैं कि मधुमक्खी पालक का जीवन तभी तब चल सकता है जब शहद का मूल्य कम से कम 120 रुपए प्रति किलो हो, लेकिन इस वक्त मूल्य लाभकारी नहीं है।

शहद के बाजार को समझने के लिए जब छोटे-बड़े व्यापारियों से सवाल पूछे गये तो उन्होंने मूल्य में गिरावट की बात तो मानी लेकिन इसके कारणों को खुलकर नहीं बताया। सबका यही कहना था, ''सुनने में आया है कि शहद में शुगर सिरप (चीनी) मिलाया जा रहा है। चावल व अन्य फसलों से बना यह सिरप प्रयोगशाला की किसी भी जांच को पास कर सकता है। कंपनियां थोड़े से शहद में शुगर सिरप मिलाकर मोटा मुनाफा कमा रही हैं।'' यह काम कौन कर रहा है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया, सुनने में आया है कि चीन की कंपनियों ने सिरप बनाने की इस तकनीक की फैक्टरियां भारत में स्थापित की हैं। सहारनपुर के एक प्रमुख व्यापारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर खुलासा किया कि उसने सुना है कि चीन की कंपनियों ने उत्तराखंड के जसपुर, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) के धामपुर और पंजाब के बटाला में इस तकनीक की फैक्टरियां लगाई हैं। रामपुर के एक व्यापारी ने इसकी पुष्टि की लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं बताया। इस व्यापार की अगर तह में भी जाया जाए तो इससे जुड़े व्यवसायी कह सकते हैं कि शुगर सिरप का उत्पादन कन्फेक्शनरी और अन्य उद्योगों के लिए किया जा रहा है। यह वैध भी है। इसी के साथ कहानी पर लगभग विराम लग जाता। मिलावट पकड़ने के लिए जैसे-जैसे परीक्षण विकसित हो रहे हैं, वैस-वैसे उद्योग भी मिलावट के नए रास्ते खोज रहे हैं।

प्रयोगशाला के परीक्षणों को मात देने के लिए मिलावट का कारोबार समय के साथ लगातार विकसित हुआ है। शहद की धोखाधड़ी दुनियाभर में चिंता का विषय है। भारत में सरकार को पता है कि शहद के कारोबार में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है लेकिन वह इस बारे में किसी को नहीं बता रही। शहद की शुद्धता के लिए मानकों में बार-बार बदलाव हुए हैं

सरकार ने निर्यात की जाने वाली शहद की अतिरिक्त और उन्नत जांच को अनिवार्य बनाया है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन ने वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य शहद की परिभाषा दी है। इसके अनुसार, ''शहद मधुमक्खियों द्वारा तैयार प्राकृतिक मिठास वाला तत्व है जो पौधों के परागण से अथवा पौधों के जीवित अंगों को अलग करके अथवा जीवित पौधों को चूसने वाले कीटों से हासिल होता है। मधुमक्खी इसे जमा, ट्रांसफॉर्म, डिहाइड्रेट और भंडारण कर छत्ते में इसे पकाती और परिपक्व करती है।'' इसलिए अगर शहद में शुगर यानी चीनी की मिलावट कर दी जाए तो वह शहद नहीं मानी जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि जो शहद हम खा रहे हैं, क्या उसमें शुगर मिली हुई है?

ऐसा लगता है कि हमारे खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को भी कुछ गड़बड़ी का अंदेशा जरूर है। वही वजह है कि पिछले कुछ सालों में उसने शहद के गुणवत्ता मानकों को एक नहीं बल्कि दो बार संशोधित किया है और गुणवत्ता के संबंध में उद्योगों को एक के बाद एक दिशा निर्देश भेजे हैं। हर बार बदलाव एक न एक शुगर की मिलावट को पकड़ने के लिए किया गया। एफएसएसएआई ने शुगर सिरप के आयात के नियमन का आदेश भी जारी किया है क्योंकि उसे अंदेशा था कि इसका इस्तेमाल मिलावट में किया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि या तो एफएसएसएआई को इस गोरखधंधे के बारे में पता है और उसने हमें यानी उपभोक्ताओं को अंधेरे में रखा है या उसे लगता है कि वह शहद की धोखाधड़ी का पता लगाकर उसे रोक देगा। **सोनल धींगरा**

सीएमडी में 'सीसीएल सेफ्टी बोर्ड'कीबैठक संपन्न

रांची संवाददाता : सीसीएलमुख्यालय, रांची मेंसीसीएल के सीएमडी पी.एम. प्रसाद की अध्यक्षता में 'सीसीएल सेफ्टी बोर्ड'की बैठक का आयोजन कियागया। बैठक मेंसीसीएल के निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के.श्रीवास्तव,निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह, सेफ्टी बोर्ड के माननीय सदस्यगण-सर्वश्री लखन लाल महतो, आर.एन.सिंह, जे.पी. झा, आर. इगनासस, एम.के. रजक, विकास कुमार, अरूण कुमार सिंह सहित सीसीएल मुख्यालय के विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्षएवं सेफ्टी विभाग के महाप्रबंधक श्री एस.वी. मराठे पूरी टीम के साथ सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुये बैठक में भाग लिये। साथ ही निदेशक (कार्मिक) श्री विनय रंजन, सभी क्षेत्रों के क्षेत्रिय महाप्रबंधक एवं उनकी टीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिए।

बैठक के प्रारंभ में दिवंगत श्रमिकों/कोरोना योद्धाओं को एक मिनट का मौन रखकर उन्हें विनम्र श्रद्धांजली दी गयी। इस अवसर पर सीएमडी पी.एम. प्रसाद ने उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण एवं अधिकारियों का स्वागत करते हुये कहा कि खान सुरक्षा सीसीएल की प्राथमिकता है और सीसीएल में कोयला उत्पादन और खान सुरक्षा साथ-साथ चल रहा है। सीसीएल में सुरक्षा के सभी मापदंडों का पालन किया जा रहा है। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में फैटल एक्सीडेंट नहीं हुआ है और हम सभी के प्रयास से भविष्य में भी कोई दुर्घटना नहीं हो ऐसा हमारी टीम का प्रयास रहेगा।

निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में कंपनी निरंतर प्रयास कर रही है कि श्रमिक बंधुगण को कंपनी की ओर से सुरक्षा संबंधित सुविधा और सुरक्षा मापदंड पर उन्हें समय-समय पर नवीनतम जानकारी मिलती रहे। निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह ने भी अपने संबोधन में बल दिया कि कंपनी तभी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है जब सुरक्षा संबंधित मापदंड में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन हो।

निदेशक (कार्मिक) विनय रंजन ने उपस्थित सभी को संबोधित करते हुये कहा कि कंपनी में कार्यरत सभी के लिए सेफ्टी महत्वपूर्ण है और हम सभी को दैनिक कार्य में भी सेफ्टी को अभिन्न अंग समझना चाहिए।

महाप्रबंधक(सेफ्टी),एस.वी. मराठेने सभी का स्वागत करते हुये पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर), सैलियंट फीचर्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि खान सुरक्षा से संबंधित 7 (सात) वीडियो क्लीप निर्माण किया गया है जिसके माध्यम से डिपार्टमेंटल और कॉंट्रेक्चुअल वर्कस को निरंतर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के माध्यम से ऐसे श्रमिकों को जागरूक किया जा रहा है जिनके पास मोबाईल की सुविधा नहीं है।

अवसर विशेष पर विभिन्न क्षेत्रों से सीसीएलसेफ्टीबोर्डके माननीय सदस्यो ंने खान सुरक्षा संबन्धित अपने-अपने बहुमूल्य विचार एवं सुझाव दिये। कार्यक्रम को सफल बनाने में महाप्रबंधक(सेफ्टी),एस.वी. मराठेएवं उनकी टीम- सर्वश्री अवनीश कुमार, राजीव शरण, राजेश खन्ना, नीरज कुमार, पी.के. सोरेन, मनीष मोहन, वी.पी. सिंह, अशोक कुमार, बरकत अली, आर.पी. सिन्हा का सक्रिय भूमिका रही।

रेल प्रबंधक नीरज अंबष्ठ ने विजेताओं को किया पुरस्कृत

रांची :मंडल रेल प्रबन्धक नीरज अंबष्ठ ने राजभाषा पखवाड़ा 2020 प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया । राजभाषा पखवाड़ा 2020 के दौरान रांची रेल मण्डल में विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। यह पहला अवसर था जब राजभाषा पखवाड़ा में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन ऑनलाइन किया गया । दिनांक 04.12.2020 को निबंध प्रतियोगिता, कविता लेखन प्रतियोगिता और सुलेख प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबन्धक, नीरज अंबष्ठ ने कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्रशस्ति पत्र एवं नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर अपर मण्डल रेल प्रबन्धक (इन्फ्रा.) अजीत सिंह यादव, राजभाषा अधिकारी श्रीमती रीता कायम सहित राजभाषा विभाग के कर्मचारीगण उपस्थित थे।

सीएमपीडीआई के 3 सदस्यों को सम्मानित किया गया

रांची : 30 नवम्बर, 2020 को सेवानिवृत्त हुए सीएमपीडीआई परिवार के 3 सदस्यों को आज संस्थान के ''कांफ्रेंस हॉल'' में आयोजित एक सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। इनमें एन0 रामाकृष्णा-पूर्व महाप्रबंधक (भू-विज्ञान), अमित जना-पूर्व महाप्रबंधक (ईएंडएम)एवं बिरसा उरांव-पूर्व फोरमैन (मेकनिकल) शामिल हैं।इस मौके पर सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एस0 सरन, निदेशक (तकनीकी/आरड-ीएंडटी)आर0एन0 झा एवंनिदेशक (तकनीकी/सीआरडी) एस0 के0 गोमास्ताने सेवानिवृत्त कर्मियों को पुष्पगुच्छ, मान-पत्र, प्रतीक चिह्न व शॉल देकर कम्पनी की ओर सम्मानित किया।

पिठौरिया में किसान पार्टी ने किसानों पर लाठी चार्ज एवं वाटर कैनन प्रहार पर विरोध जताया

रांची :हरियाणा पंजाब के किसानों के ऊपर पिछले दिनों लाठीचार्ज और वाटर कैनन की बौछार के विरोध में पिठोरिया किसान पार्टी ने एकदिवसीय धरने का आयोजन किया। जिसमें सबों की एकराय थी कि अनाज उपजाने वाले किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए और सरकार को वार्ता की आखिरी उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहिए था। इस धरना प्रदर्शन को किसान पार्टी के बैनर तले आयोजित किया गया। किसान पार्टी 1946 से गठित है। किसान पार्टी के इस अध्यक्ष रंजीत साहू सचिव रितेश कुमार दीपक कोषाध्यक्ष मदन साहू ऋषभ कुमार रतन गोप सफीउल्लाह अंसारी गुफरान अंसारी भाटी प्रकाश संजय ठाकुर आदि अन्य लोगों ने धरना में भाग लिया और सरकार के रवैये से नाखुश होकर अपना अपना वक्तव्य दिया

लॉकडाउन हटते ही प्रदूषण वापस लौट आया : सीएसई रिपोर्ट

इस साल लंबे समय तक लॉकडाउन के कारण पीएम 2.5 का स्तर कम रहा, बावजूद इसके सर्दियों की शुरुआत और अनलॉक होने के साथ ही प्रदूषण बढ़ गया

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) द्वारा जाड़ों में होने वाले प्रदूषण के नवंबर तक किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि लॉकडाउन और मानसून के दौरान जो हवा साफ हो गई थी, वह लॉकडाउन हटते ही और सर्दियों का मौसम आते-आते फिर से प्रदूषित हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर के निगरानी स्टेशनों से वास्तविक समय के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस साल सर्दियों में होने वाले प्रदूषण के पैटर्न में बदलाव नजर आ रहा है।

सीएसई के कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉय चौधरी कहती हैं कि भले ही 2020 में 11 महीनों के दौरान पीएम 2.5 का कुल औसत स्तर पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम रहा, लेकिन सर्दियों में पीएम 2.5 का स्तर दिल्ली-एनसीआर में वायु के स्तर को बहुत खराब तथा गंभीर बना सकता है।

उन्होंने कहा कि यह एक विशिष्ट पूर्वानुमान है, जब सर्दियों में स्थानीय स्रोतों से लगातार उत्सर्जन और बायोमास जलने से होने वाले प्रदूषण और मौसम संबंधी परिवर्तनों के कारण यह हो रहा है। लेकिन इस वर्ष, पिछले वर्ष की तुलना में स्मॉग की घटनाओं में कमी दिखाई दी है, जो पैटर्न में एक तरह का बदलाव है, पिछले वर्ष पराली जलने के दिनों की संख्या भी अधिक थी, जिससे प्रदूषण में वृद्धि हुई। ऐसे दिन भी थे, जब बिना बारिश के प्रदूषण का स्तर गिरकर मध्यम स्तर पर पहुंच गया, हालांकि इन दिनों में हवा तेजी से बह रही थी।

सीएसई की सस्टेनेबल सिटीज टीम में प्रोग्राम मैनेजर अविकल सोमवंशी का कहना है कि यह इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रदूषण करने वाले क्षेत्रों में सुधार और कार्रवाई करने की जरुरत है, जिनमें वाहन, उद्योग, बिजली संयंत्रों और अपशिष्ट प्रबंधन आदि शामिल हैं। इनमें तेजी से सुधार करना होगा, ताकि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके।

सीएसई विश्लेषण के मुख्य बिंदु

लॉकडाउन के कारण साल भर पीएम 2.5 का औसत स्तर कम रहा लेकिन यह सर्दियों में होने वाली वृद्धि को रोक नहीं सका। ग्रीष्मकालीन लॉकडाउन और मानसून के दौरान आर्थिक गतिविधियों पर लगी रोक की वजह से इस साल नवंबर तक कुल मिलाकर पीएम 2.5 का औसत पिछले साल की तुलना में काफी कम है, लेकिन सर्दियों में होने वाले प्रदूषण की शुरुआत के साथ अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने से अक्टूबर और नवंबर के दौरान पीएम 2.5 का स्तर फिर बढ़ गया। अगस्त का महीना सबसे साफ रहा जो कि एक रिकॉर्ड है, प्रदूषण का स्तर बढ़ने से हाल के वर्षों की तुलना में नवंबर माह सबसे प्रदूषित रहा। प्रदूषण के स्तर में दिल्ली में 9.5 गुना वृद्धि हुई, गाजियाबाद में 11 गुना तक वृद्धि हुई, इसके बाद नोएडा (9.2 गुना), गुरुग्राम (6.4 गुना) और फरीदाबाद (6.2 गुना) है। लॉकडाउन के दौरान वायु प्रदुषण में आई कमी को बरकरार नहीं रखा जा सका, जब तक वाहनों, उद्योग, बिजली संयंत्रों और कचरे से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रणालीगत बदलाव नहीं किया जाता तब तक ऐसा होता रहेगा।

सीएसई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के शहरों और कस्बों के वार्षिक औसत की तुलना दिल्ली और चार बड़े शहर (गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद) से की। इससे पता चलता है कि पीएम 2.5 के वार्षिक औसत स्तर के बहुत कम होने पर, एनसीआर के अन्य छोटे शहरों और कस्बों में सर्दियों के दौरान स्तर अधिकतम, लगभग समान होता है, जब पूरे क्षेत्र में हवा बहनी बंद हो जाती है। यहां तक कि दिल्ली, जहां हाल के वर्षों में सालाना आधार पर वार्षिक औसत स्तर में गिरावट देखी गई है। सर्दियों के दौरान यहां प्रदूषण का स्तर अधिक पाया गया है।

सर्दियों की शुरुआत के साथ ही वायु गुणवत्ता अधिक जहरीली हो जाती है, पीएम 10 में सूक्ष्म कणों की (पीएम 2.5) की हिस्सेदारी बढ़ जाती है। पीएम 10 एकाग्रता में महीन कणों का हिस्सा हवा की विषाक्तता को निर्धारित करता है। दिलचस्प बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान, जब सभी कणों ने पीएम 10 के स्तर को कम कर दिया था, जिससे पीएम 2.5 का स्तर भी नीचे आ गया था। इस साल स्मॉग की घटना का पैटर्न अलग है। तकनीकी रूप से एक स्मॉग एपिसोड को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत आपातकालीन कार्रवाई के उद्देश्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, जब पीएम 2.5 का स्तर लगातार तीन दिनों तक "गंभीर" श्रेणी में बना रहता है। इस क्षेत्र में इस साल (नवंबर 7-10, 2020) पिछले साल (31 अक्टूबर-नवंबर 3, 2019 और नवंबर 12-15, 2019) की दो घटनाओं की तुलना की गई जिसमें से एक को गंभीर स्मॉग घटना माना गया है।

इस साल दिवाली के पटाखों से प्रदूषण, पराली जलाने और स्थानीय धुएं के मिल जाने से दिवाली के दिन (नवंबर 14, 2020) प्रदूषण स्तर को गंभीर और खतरनाक बना दिया था। लेकिन यह लंबे समय तक नहीं टिक पाया एक छोटी सी बारिश ने इसे जल्दी ही साफ कर दिया। नवंबर 2020 में ऐसे दिन थे जब बारिश के बिना हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। 2020 में नवंबर की दूसरी छमाही के दौरान तीन दिन ऐसे थे जब दिल्ली में वायु गुणवत्ता के गुणवत्ता सूचकांक श्रेणी में सुधार हुआ था।

फोटो न्यूज

मनुष्य सक्षम हैं, पर कहां जायेंगे ये बेजुबान?

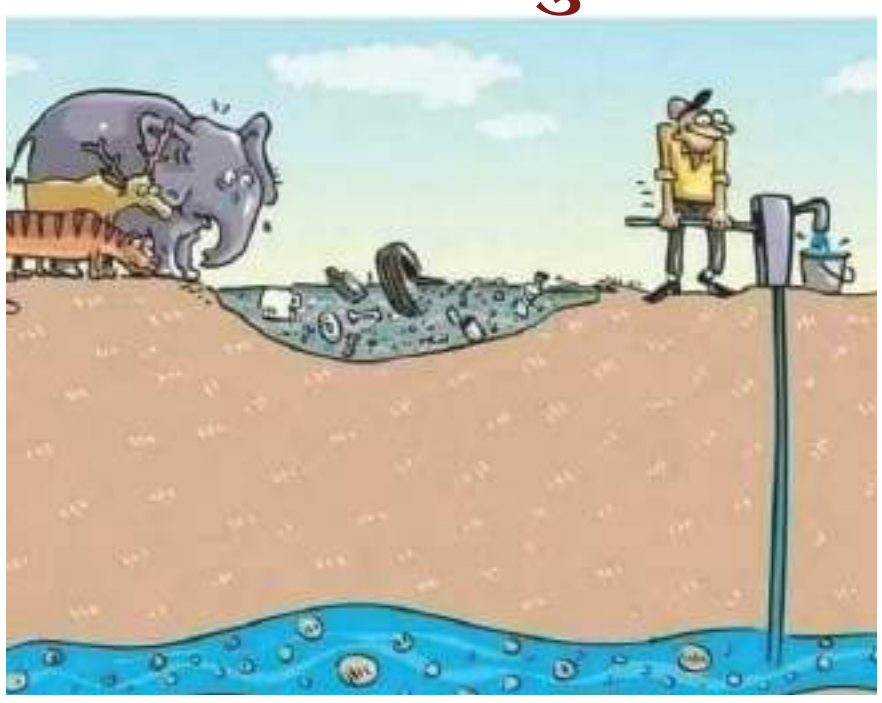

ऐसे भी जान बख्श सकते हैं किसी पेड़ की

स्वास्थ्य ही असली धन है

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

बचपन से हम ये कहावत सुनते आये है कि "स्वास्थ्य ही असली धन है" लेकिन शायद समय के साथ हम ये बात भूल गए है,तभी तो धन को अर्जित करने मे हमने अपने स्वास्थ्य को पीछे छोड़ दिया है

आधुनिक जीवनशैली के अधीन हो गए है हम, हर व्यक्ति सिर्फ भाग रहा है।हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि टेक्नॉलजी की मदद से जिन्दगी कितनी आसान और आरामदायक हो सकती है। इसी आरामदायक जीवन ने बीमारियो नेवता दिया है।हमने कभी ये सोचा है कि अगर हमारे पास बहुत सारा धन हो और हम बीमार हो तो हम क्या हम उस धन का आनंद ले सकते है ?बिल्कुल नही परन्तु अगर हमारे पास स्वस्थ शरीर और शांत मन हो तो हम विकट से विकट परिस्थिति का डट के सामाना कर सकते है।हमे जीवन यापन के लिए पैसे की आवश्यकता होती है परन्तु उसको अर्जित करने मे अपने स्वास्थ्य को ताक पर नही रखना चाहिए।

मानसिक गतिविधियों ने शारीरिक गतिविधियों की जगह ले ली है।एक बच्चे को बचपन मे ही किताबो की बोझ मे दबा दिया जाता है । बचपन से ही कक्षा मे अव्वल आने की बात बताई जाती है और बच्चे खेल कूद से काफी दूर हो जाते है।हम यह बात भूल जाते है कि शारीरिक विकास भी उतना ही जरूरी है जितना की मानसिक विकास। एक स्वास्थ्य शरीर मे ही स्वास्थ्य दिमाग होता है।अपने पूर्वजो को अगर हम याद करे तो हम देखेंगे की वो कितने और फुर्तीले थे और इसका एक ही कारण था ,एक अच्छी जीवनशैली ।हमे भी एक अच्छी जीवनशैली अपनानी चाहिए।कुछ अच्छी आदतें हम भूल गए है जैसे सुबह जल्दी उठना ,घर का बना ताजा खाना खाना ,पैदल चलना,व्यायाम करना ,समय पर सोना और कम मे खुश रहना।कुछ छोटी छोटी बदलाव करके हम एक स्वास्थ्य शरीर और स्वास्थ्य मन दोनो ही पा सकते है।

गर्म जलवायु के प्रभाव से ब्रह्मपुत्र नदी में होगी बाढ़ की विभीषिका

एजेंसियां

एक नए अध्ययन में दक्षिण एशिया की शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी में जल प्रवाह के सात शताब्दियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से पता चलता है कि वैज्ञानिकों द्वारा जलवायु के गर्म होने से नदी में आने वाली विनाशकारी बाढ़ की क्षमता को कमतर आंका गया है। इस रहस्य का पता पेड़ के छल्लों (ट्री रिंग्स) की जांच से होता है, जिसमें वर्षा के पैटर्न को आधुनिक यन्त्रों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड से सदियों पहले हुई घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है।

शोधकर्ता इस बात से सहमत हैं कि गर्म होती जलवायु मानसूनी बारिश की गति को तेजी से बढ़ाएगी जिससे ब्रह्मपुत्र का जल प्रवाह बढ़ेगा। नदी के प्रवाह में आए पिछले प्राकृतिक बदलाव मुख्य रूप से केवल 1950 के दशक के डिस्चार्ज-गेज रिकॉर्ड पर आधारित है। नदी के जलक्षेत्र में और उसके आसपास प्राचीन पेड़ों के छल्लों के आधार पर किए गए नए अध्ययन से पता चलता है कि 1950 के दशक के बाद की अवधि वास्तव में 1300 के दशक के बाद से सबसे शुष्क में से एक थी। छल्ले बताते हैं कि अतीत में यह अवधि बहुत अधिक नम रही है, जो प्रकृति द्वारा संचालित है तथा दशकों या सदियों से होती आ रही है। विनाशकारी बाढ़ वैज्ञानिकों ने जितना सोचा था शायद उससे अधिक बार आएगी यहां तक कि मानव-जनित जलवायु परिवर्तन का कोई भी प्रभाव बहुत बड़ा होगा। यह अध्ययन नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

सूखे की जद में है देश का 68 फीसदी हिस्सा

एजेंसियां

पिछले 15 सालों में चरम सूखे की स्थिति में भी वृद्धि हुई है। इससे अब तक करीब 79 जिले प्रभावित हो चुके हैं। इसके चलते हर साल करीब 14 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस अवधि में सूखा प्रभावित जिलों का वार्षिक औसत 13 गुना बढ़ गया है। एनडीएमए के अनुसार देश का करीब 12 फीसदी हिस्सा बाढ़ और 68 फीसदी हिस्सा सूखे की जद में है। इसी तरह देश की करीब 80 फीसदी तटरेखा पर चक्रवात और सुनामी का खतरा है।

इसी तरह 2005 के बाद से हर साल 24 जिलों पर चक्रवातों की मार पड़ रही है। इन वर्षों में करीब 4.25 करोड़ लोग तूफान और चक्रवातों से प्रभावित हुए हैं। यदि पिछले एक दशक को देखें तो इनका असर अब तक करीब 258 जिलों पर पड़ चुका है। देश में पूरी तटरेखा के आसपास पुरी, चेन्नई, नेल्लोर, उत्तर 24 परगना, गंजम, कटक, पूर्वी गोदावरी और श्रीकाकुलम पर इन चक्रवातों का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। जिसके लिए जलवायु परिवर्तन, भूमि उपयोग में आ रहा बदलाव और वनों का विनाश मुख्य रूप से जिम्मेवार है। यदि 1970 से 2019 के बीच चक्रवात की घटनाओं पर गौर करें तो इन वर्षों में यह घटनाएं 12 गुना बढ़ गई हैं।

इस रिपोर्ट में एक हैरान कर देने वाली बात यह सामने आई है कि पहली जिन जिलों में बाढ़ आती थी अब वहां सूखा पड़ रहा है। इसी तरह जो जिले पहले सूखा ग्रस्त थे अब वो बाढ़ की समस्या से त्रस्त हैं। आपदाओं की प्रवृति में हो रहा यह बदलाव 40 फीसदी जिलों में अनुभव किया गया है। यदि इसकी प्रवृति की बात करें तो जो जिले बाढ़ से सूखाग्रस्त बन रहे हैं उनकी संख्या सूखे से बाढ़ग्रस्त बनने वाले जिलों से कहीं ज्यादा है जो दिखाता है कि देश में सूखे का कहर बढ़ रहा है।

रिपोर्ट में इसके लिए देश में क्षेत्रीय स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ भूमि उपयोग में किए जा रहे बदलावों, वनों के विनाश, मैन्ग्रोव और वेटलैंड पर हो रहे अतिक्रमण को जिम्मेवार माना है।

भारत में प्रति व्यक्ति सीओ2 उत्सर्जन है बहुत कम

यदि भारत के उत्सर्जन को देखें तो 2019 के दौरान भारत में 3.7 गीगाटन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ था। इस आधार पर भारत, चीन (14 गीगाटन), अमेरिका (6.6 गीगाटन) और यूरोप और यूके (4.3 गीगाटन) के बाद चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। जबकि यदि भारत में प्रति व्यक्ति द्वारा किए जा रहे उत्सर्जन पर गौर करें तो यह 2.7 टन सीओ2 प्रति व्यक्ति है, जोकि अंतराष्ट्रीय औसत (6.8 टन सीओ2इ प्रतिव्यक्ति) से भी काफी कम है।

साथ ही यह चीन (9.7 टन सीओ2इ प्रतिव्यक्ति), अमेरिका (20 टन सीओ2इ प्रतिव्यक्ति), यूरोप और यूके (8.6 टन सीओ2इ प्रतिव्यक्ति), रूस (17.4 टन सीओ2इ प्रतिव्यक्ति) और जापान (10.7 टन सीओ2इ प्रतिव्यक्ति) से भी कई गुना कम है। यदि भारत द्वारा 2010 के बाद से किए जा रहे उत्सर्जन की बात करें यह हर वर्ष औसतन 3.3 फीसदी की दर से बढ़ रहा था। जबकि 2019 में उत्सर्जन की दर में कमी दर्ज की गई है जब इसमें हो रही वृद्धि 1.3 फीसदी दर्ज की गई थी। भारत अपने उत्सर्जन में

कमी करने के लिए कई प्रयास कर रहा है इसी दिशा में उसने 2020 के पहले छह महीनों में कोई नया थर्मल पावर प्लांट स्थापित नहीं किया है। यही वजह है कि कोयले से उत्पन्न हो रही ऊर्जा में करीब 0.3 गीगावाट की कमी आई है। हालांकि भारत की रणनीति भविष्य में भी कोयला से ऊर्जा प्राप्त करने की है। यही वजह है कि 2020 में भारत का घरेलू कोयला उत्पादन रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है।

भारत सौर ऊर्जा पर भी विशेष ध्यान दे रहा है, 2022 तक अपने कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ाने और 25 गीगावॉट क्षमता विकसित करने के लिए निवेश को बढ़ाने की विस्तृत पीएम कुसुम योजना बनाई है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी को 2022 तक 175 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी विशेष ध्यान दे रहा है जिससे उससे हो रहे उत्सर्जन को सीमित किया जा सके।

भारतीय रेलवे ने 2023 तक अपने पूरे नेटवर्क का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है और 2030 तक रेलवे को उत्सर्जन मुक्त करने का लक्ष्य भी तय किया है।

भारत के 30 शहर अगले तीन दशकों में झेलेंगे गंभीर जल संकट

एजेंसियां

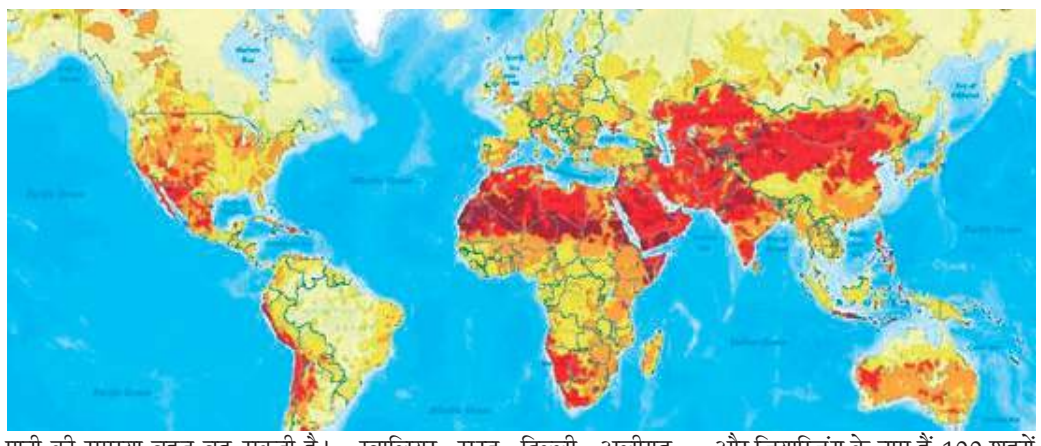

कहते हैं 'बिन पानी सब सून' और अब यह कहावत देश और दुनिया के कई शहरों पर लागू होने जा रही है. आपको पता है दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन की बात हो या भारत के चेन्नई की, जलसंकट भारत ही नहीं, दुनिया भर में किस कदर गहरा चुका है। इस मुद्दे पर विश्व वाइल्डलाइफ फंड के ताजा सर्वे ने चिंता की लकीरें और गाढ़ी कर दी हैं। इस सर्वे में कहा गया है कि अगले 30 सालों में दुनिया के 100 शहरों में बेहद गंभीर जलसंकट होगा और इस लिस्ट में 30 शहर भारत के हैं।

करीब 35 करोड़ की आबादी होगी, जो यह संकट झेलेगी। विश्लेषण में साफ कहा गया है कि अब भी वक्त है, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज की दिशा में सही और पुख्ता कदम नहीं उठाए गए तो 2050 तक करोड़ों लोगों को पानी के लिए तरसना होगा।

30 शहर हैं लिस्ट में

भयानक जलसंकट की चेतावनी जिन 100 शहरों के लिए जारी की गई है, उनमें भारत के दो शहर जयपुर और इंदौर क्रमशः 45वें और 75वें नंबर पर हैं. इस लिस्ट के समानांतर एक और लिस्ट बनाई गई है, जिन शहरों में कुछ दशकों बाद पानी की समस्या बहुत बढ़ सकती है। इस लिस्ट में भारत के 28 शहर शामिल हैं।

भारत में जलसंकट, दुनिया में जलसंकट, शहरी जलसंकट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टभारतीय शहरों में जयपुर और इंदौर के सामने जलसंकट का खतरा सबसे भयानक बताया गया।

अमृतसर, पुणे, श्रीनगर, कोलकाता, बेंगलूरु, मुंबई, कोझिकोड, विशाखापटनम, ठाणे, वडोदरा, राजकोट, कोटा, नाशिक, अहमदाबाद, जबलपुर, हुबली धारवाड़, नागपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, धनबाद, भोपाल, ग्वालियर, सूरत, दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ और कानपुर के नाम 28 शहरों की सूची में शामिल हैं। सभी तीस शहरों में से लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर और अहमदाबाद लिस्ट में टॉप रहे हैं। इस तरह की योजनाओं से भविष्य में बाढ़ जैसी समस्याओं से बचा जा सकेगा। मक्का, चीन के टांगशान और सऊदी अरब के ही अद दम्माम और रियाद शहर भी लिस्ट में शामिल हैं।

इस लिस्ट में सबसे पीछे 10 शहरों में सिएरा लिओन के फ्रीटाउन, चीन के ताइयुआन, वेनलिंग, गुइयांग, यानताई और जियाग्जिंग के नाम हैं.100 शहरों की लिस्ट में अन्य प्रमुख शहरों में बीजिंग, जकार्ता, जोहानिसबर्ग, इस्तांबुल, हांग कांग और रिओ डि जेनेरियो के नाम भी हैं. इन तमाम शहरों में शहरी नम भूमि और वॉटरशेडों के सही प्रबंधन की सलाह दी गई है. ऑगेर्नाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट, पानी प्लांटों और सप्लाई नेटवर्कों के लिए ही कम से कम सालाना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च करना ही समस्या का हल होगा.

2040 तक 3 टेराटन हो जाएगा इंसानी निर्माण

एजेंसियां

धरती पर बढ़ता इंसानी निर्माण का बोझ, प्राकृतिक तत्वों से हुआ भारी

2020 के अंत तक इंसानी निर्माण का भार प्राकृतिक तत्वों के वजन से ज्यादा हो जाएगा। अनुमान है कि इंसान लगभग 1.1 टेराटन के बराबर वस्तुओं का निर्माण कर चुका है

धरती पर नए युग को मानव युग (एंथ्रोपोसीन) के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे लिए कोई बड़े गर्व की बात नहीं। जिस तरह से मानव ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, यह नाम सटीक ही बैठता है। आज अपने श्रेष्ठ दिमाग के बल पर मानव पृथ्वी पर सबसे कामयाब जीव है, लेकिन उसकी इस कामयाबी का खामियाजा धरती पर हर जीव को उठाना पड़ रहा है।

आज शायद ही ऐसा कुछ हो जिसे मनुष्य ने अपनी जरूरतों के लिए नुकसान न पहुंचाया हो और उसका दोहन न किया हो। प्रकृति के दोहन की इस कहानी में अब एक नया अध्याय और जुड़ गया है। हाल ही में अंतराष्ट्रीय जर्नल नेचर में छपे एक शोध से पता चला है कि धरती पर इंसान इतना ज्यादा निर्माण कर चुका है कि वो 2020 के अंत तक प्राकृतिक तत्वों से भी ज्यादा भारी हो जाएगा। मानव द्वारा निर्मित इन वस्तुओं में प्लास्टिक, लोहा, निर्माण, ईंटें, कंक्रीट आदि सभी

कुछ शामिल है। यह शोध इजरायल के वीज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, मानव-निर्मित वस्तुओं का वजन दुनिया के कुल बायोमास के लगभग 3 फीसदी के बराबर था, जोकि 2020 में प्राकृतिक बायोमास से भी ज्यादा करीब 1.1 टेराटन हो जाएगा। दुनिया में हर व्यक्ति के लिए उसके शरीर के वजन से अधिक वस्तुओं का निर्माण प्रत्येक सप्ताह हो रहा है। इस समझने के लिए शोधकर्ताओं ने 1900 के बाद से अब तक निर्मित हर वस्तु के वजन का अनुमान लगाने का प्रयास किया है और उसकी तुलना पृथ्वी पर मौजूद सभी जैविक तत्वों और जीवों के वजन (जिसे बायोमास के रूप में जाना जाता है) से की है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्लास्टिक की बोतलों से लेकर ईंटों और कंक्रीट जिसका इस्तेमाल हम करते हैं उनका वजन हर 20 वर्षों में दोगुना हो रहा है। जबकि इसके विपरीत प्राकृतिक तत्वों का वजन कम हो रहा है। जंगलों और जीवों का विनाश जिसका मुख्य कारण है।

शोध के अनुसार अकेले प्लास्टिक का वजन ही धरती पर मौजूद सभी जीव-जंतुओं के वजन से ज्यादा है। जहां जमीन और समुद्र में मौजूद सभी जीवों का वजन करीब 4 गीगाटन है जबकि अकेले प्लास्टिक का वजन 8 गीगाटन के करीब है। उसी तरह सभी पेड़ों और झाड़ियों का वजन 900 गीगाटन है जबकि उसके विपरीत सभी बिल्डिंग्स और रोड एवं अन्य निर्माण का वजन करीब 1,100 गीगाटन है। अनुमान है कि यदि इंसान इसी दर से निर्माण करता रहा तो 2040 तक इंसानों द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं का वजन 1.1 टेराटन से बढ़कर 3 टेराटन हो जाएगा। जिसका मतलब है कि आज इंसान 30 गीगाटन हर वर्ष की दर से वस्तुओं का निर्माण कर रहा है।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।